

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार, 03 मई 2023 वर्ष-6, अंक-98 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Web site : [www.krantisamay.com](http://www.krantisamay.com) & [epaper.krantisamay.com](http://epaper.krantisamay.com) [www.facebook.com/krantisamay1](https://www.facebook.com/krantisamay1) [www.twitter.com/krantisamay1](https://www.twitter.com/krantisamay1)

केजरीवाल के गृह राज्य  
हरियाणा में क्यों कुंद हो  
हो आप का धार

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पिछले साल जब पंजाब विधानसभा चुनावों में परचम लखराया तो पड़सी राज्य हरियाणा में भी उसकी सियासी हसरतें कुलाचे माने लगीं लेकिन सालभर के अंदर ही आप की सियासी हसरत दम तोड़ती नजर आ रही है। आप ने इस साल पहले जनरी में अपनी राज्य झड़क को धंग कर दिया। अब, पार्टी ने एकविं नार पारिवारिक अध्यक्ष को भी गवर्नर दिया है।

हरियाणा आप संयोजक अविंश के जरीवाल का गृह राज्य है। जून 2022 में, आप ने इस्माइलाबाद नारपालिका समिति के अध्यक्ष पद पर जारी हसरिल की थी लेकिन पिछले शुक्रवार को नारपालिका अध्यक्ष नियोग ने आप को झटका देते हुए उपमुखमंत्री दुर्योग चौटाल की जनरियक जनरी पार्टी (जेपी) का दामन थाम लिया। जेपी में शमिल होने पर गर्ने ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, +विपक्षी दल से अकेले अध्यक्ष होने के नाते काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे उस काम के लिए दफतरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो सत्ता पक्ष की ओर से तरीके सिफर एक फोन कॉल करने से हो जाता। वहाँ सड़कों और बेंचों के निर्माण के लिए सिफर टेंडर निकालने में ही आठ महीने लग गए। आप निशा गंगा पर अयोग्यता का मामला चलाने से बच रही है और इसे बड़ा मुद्दा नहीं मान रही। दूसरी तरफ, गंगा के पति पुनर्नाम गंगा ने दावा किया है कि आप ने आज तक अपने राज्य संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पार्टी में कई खास हलचल देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आगे साल लोकसभा के साथ ही हारियाणा में विधान सभा चुनाव भी होने हैं। बता दें कि हरियाणा में झाड़ की संभावना को देखते हुए ही पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अंशोक तवर, पूर्व राज्य मंत्री निर्मल सिंह और उत्तरी बेटी चिंता बरावा जैसे नेता आप में शामिल हुए थे।

## जम्मू-कश्मीर-पहली बार बाहरी लोगों को 96 फ्लैट दिए जाएंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना के 336 फ्लैट्स आवंटन की प्रक्रिया शुरू

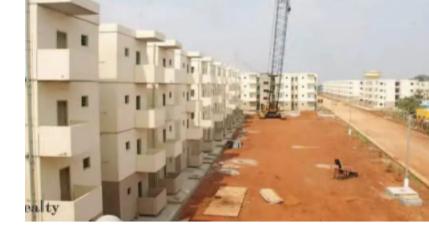
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में पहली बार बाहरी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (इंडिल्यूएस) के लोगों को 336 फ्लैट्स के आवंटन के लिए आवेदन आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस महीने के अंत तक पहले बैच में 96 फ्लैट्स दिए जायेंगे। हर फ्लैट 290 वर्ग फुट का है, ये 2200 रुपए प्रति महीने किए एं पर आवंटित होंगे।

श्रूतिआत में 3 साल के लिए आवंटन बाद में बढ़ागा

शुरूआत में तीन साल के लिए आवंटन होगा, इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। 2020 में सरकार ने एक लाख अफोडेंबल मकानों के निर्माण का ऐलान किया था। इसके तहत 10 हजार आवास बाहरी लोगों को आवंटित किए जाएंगे।

फिलहाल, जम्मू संघाग के पांच क्षेत्रों में से जम्मू जिले में चार और सांसार में एक जबकि कश्मीर संघाग के तीन क्षेत्रों गांदरबल में दो और बांदीपोरा में शामिल हुए थे।

एक स्थान पर इन अफोडेंबल आवासों का निर्माण होना है।



बाहरी लोगों में ये शामिल-जिन लोगों को इन फ्लैट्स का आवंटन होना है उनमें श्रमिक, शहरी गरीब (स्ट्रीट वैडेंट, विश्वा चालक और अन्य कामगार), मंडी और दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले, दीर्घ अवधि के लिए आगे वाले पटक, विद्यार्थी एवं इस श्रेणी के अन्य लोग शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के 336 फ्लैट्स आवंटन की प्रक्रिया शुरू

केंद्रीय कारागार तिहाड़ (रियल एसेट्स)

संख्या-1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

## जन-मन की बात

किसी कार्यक्रम का सौवां पडाव निश्चय ही सफलता का सूचक कहा जा सकता है। इसी पैमाने पर प्रधानमंत्री का रेडियो के जरिये जनता से सीधे संवाद के कार्यक्रम 'मन की बात' को सार्थक माना जा सकता है। कार्यक्रम की सौर्वी कड़ी को एक उत्सव में बदलने की मंशा को सफलता मिली भी है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी कार्यक्रम की चर्चा, भागीदारी और प्रतिभागिता हुई। जिसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र में सीधे प्रसारण के रूप में पहुंची। निस्संदेह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता हैं। उनकी आयोजनों को उत्सव में बदलने की क्षमता भी विशिष्ट ही है। इस कार्यक्रम के जरिये उन्होंने तमाम उन योद्धाओं को सामने लाने की कोशिश की जो गुमनामी में व्यवस्था बदलने के काम में लगे थे। जिनके बारे में मुख्य मीडिया में चर्चा कम ही हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना जीवन लीक से हटकर विशिष्ट बदलावों के लिये लगाया। मसलन हरियाणा में 'सेल्फी विद डॉट' मुहिम में लगे जीद के सुनील जगलान हो या हिमालयी पर्यटन स्थलों में टूरिस्टों द्वारा छोड़ गये कचरे को साफ करने वाले प्रदीप सांगवान के 'हीलिंग हिमालय' कार्यक्रम की बात हो या हरियाणा में मधुमक्खी पालन करके तमाम लोगों को रोजगार देने वाले राजकुमार कंबोज हों, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने पिछले एपिसोड में चंडीगढ़ के उस युवक का भी जिक्र किया जो लोगों से कापी-किताबें-एक्र करके निर्धन बच्चों को पढ़ाने की मुहिम में जुटा है। कोरोना काल में तमाम ऐसे लोगों का जिक्र हुआ, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में लोगों को नई राह दिखायी। निस्संदेह, मन की बात कार्यक्रम के जरिये रेडियो को भी नये सिरे से प्रतिष्ठा मिली। जो कि आज के इंटरनेट-सोशल मीडिया के दौर में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेडियो के जरिये देश के दूर-दराज के इलाकों के लोगों का इस कार्यक्रम से जु़ुनां आसान हुआ है। इसके सौर्वे एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब मैं गुजरात से दिल्ली आया तो मुझे व्यवस्थागत व सुरक्षा कारणों से अलगाव महसूस हुआ। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मेरा लोगों से काफी मिलना-जुलना होता था। तब मेरे मन में जनता से संवाद के लिये यह तरीका आया। जिसमें मुझे आशातीत सफलता भी मिली। बहरहाल, समाज में रचनात्मक बदलाव के वाहकों को सम्मान देना हमारा सामाजिक दायित्व भी है और अन्य लोगों को ऐसा करने के लिये प्रेरणा भी मिलती है। हालांकि, विपक्ष इसे इवेंट मैनेजमेंट बताता रहा है और इसे राजनीतिक लक्ष्य साधने का जरिया कहता है। साथ ही विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय के विवादित प्रश्नों व विषयों को मन की बात कार्यक्रम में शामिल नहीं करते। वे कार्यक्रम में पेश किये गये कुछ तथ्यों पर उंगली उठाते रहे हैं कि इससे समाज में ऊहापोक की स्थिति पैदा होती है क्योंकि सत्ता शीर्ष से निकले तथ्य जनमानस में प्रमाणिकता की कसौटी होते हैं। बहरहाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मन की बात जैसे कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। इसके जरिये लोग समाज में प्रेरक रचनात्मक बदलावों, सरकार की रीति-नीतियों से रुक्खर होते हैं।

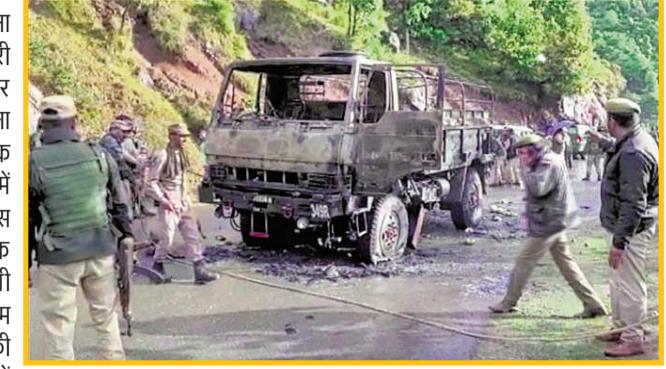
## **आज का राशीफल**

<b>मेष</b>	गुहोपयोगी वस्तुओं में बृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के कार्यों में धन खच करने के योग हैं। राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे।
<b>वृषभ</b>	परिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
<b>मिथुन</b>	आर्थिक पूर्व मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाग्यवश कुंडल घेसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। किसी अधिक मित्र या रिशेदारा से संभावना है।
<b>कर्क</b>	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परिवारिक जनों से पीड़ा मिलने के योग हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। प्रणय संबंध मधुर होंगे।
<b>सिंह</b>	व्यावसायिक योजना सफल होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। मकान सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।
<b>कन्या</b>	रोजी रोजगार की दिशा में सफलता के योग हैं। सृजनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। खान-पान में संयम रखें। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफल रहेंगे हु
<b>तुला</b>	शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। वाणी की सौम्यता आपको धन लाभ करायेगी। व्यर्थ की भागदौड़ होगी।
<b>वृश्चिक</b>	व्यावसायिक योजना सफल होगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आर्थिक उत्तमि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
<b>धनु</b>	परिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी। आत्रा देशानन्द की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा।
<b>मकर</b>	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ेगा।
<b>कुम्भ</b>	दामत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खान-पान संयम रखें। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। विराधियों का पराभव होगा।
<b>मीन</b>	जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। आपके पराक्रम में बृद्धि होगी। कोई भी महल्यपूर्ण निर्णय न लें। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा।

# कश्मीर में अत्यवरथा पर शीघ्र कार्टवाई का वक्त

गुरखचन जगत

जिस शातिराना ढंग से हमारे सैनिकों पर घात लगाकर हमला हुआ है, उससे राजौरी और पुंछ एक बार पुनः खबरों की सुर्खियों में हैं; उनमें शहीद हुए 5 सैनिकों में 4 पंजाब से हैं। कोई शक नहीं कि यह करतूत भी सीमा पार से शत्रुता निभाने वालों के निर्देशों और मदर पाये आतंकवादियों की है। इस हमले की तपसील में जाने से पहले इस क्षेत्र के इतिहास का जिक्र करना चाहूँगा। पिछली सदी के आखिरी सालों में, राजौरी, पुंछ, उधमपुर के गुल एवं महार और डोडा क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों पर और सामान्य नागरिकों (अधिकांशतः हिंदू) पर हमलों की झड़ी-सी लग गई थी। यह तमाम इलाका पीर पंजाल पर्वतमाला की जम्मू की तरफ पड़ती ढाल में पड़ता है और नीचे जाकर घाटी तक जुड़ा है। इन नरसंहारों ने जनता में दहशत भर दी और कुछ लोगों ने निघले क्षेत्रों की ओर पलायन किया। वक्त के उस बिंदु पर, आतंक फैलाने को उत्तरु ताकतें और सीमा पार बैठे उनके आकाओं की मंशा स्पष्ट हो चुकी थी। वे चाहते थे इस क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन हो जाए ताकि घाटी तक का सारा इलाका मुस्लिम बहुल बन जाए। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो इससे उधमपुर, कटुआ और जम्मू जिले के इन संभागों में अल्पसंख्यकों की गिनती आधी रह जाती। हालांकि भारत सरकार, राज्य प्रशासन, पुलिस एवं सेना समेत सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से यह घटयंत्र विफल रहा। जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने विशेष कार्यबल के साथ एक सक्षम ताकत बनकर उभरी थी, विशेषकर, जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की सामर्थ्य बनाने में। इसके अलावा, बड़े स्तर पर बनाई गई ग्राम सुरक्षा समितियां बहुत कारगर रहीं। इस मॉडल पर क्रियान्वयन आगे भी कमोबेश कायम रहा, क्योंकि जमीनी स्तर पर सुरक्षा बलों के बीच आपसी समन्वय और मिलकर काम करना बहुत बढ़िया रहा, इससे हालत काबू में बने रहे। आगे चलकर निजाम में बदलाव हुआ, अंततः अनुच्छेद 370 हटाने के साथ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हालांकि इससे सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा विप्रोव हो तो नहीं उठ खड़ा हुआ लेकिन घाटी और इसके साथ इलाके में चुप्पी और डर की दीवार खड़ी हो गई। घाटी खामोश थी, पहाड़ चुप्पे थे, लोगों के मुह सिले हुए थे। सुरक्षा बलों की उपस्थिति चहूं ओर थी। हालांकि इस सबसे घाटी में पंडितों की वापसी फिर भी न बन पाई, न ही व कामकाज करने या रहने के लिए उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। अभी तक का परिणाम यह है कि हम चुनाव तक नहीं करवा पाये और न ही राज्य का दर्जा बहाल हुआ है। बेशक, इस बीच आतंकवाद पर नकेल पड़ी और घुसपैठ भी कम रही, जमीनी सतह पर होने वाली आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई, विशेषकर जमात-ए-इस्लामी की, किंतु फिर



भी पंडितों को विशेष रूप से निशाना बनाकर की गई हत्याएं जब-तब जारी रहीं, जो कि घाटी से एक बार फिर पलायन करने को काफी था। सुरक्षा बल काफी सक्रिय रखे किंतु राजनीतिक गतिविधियों की अनुपस्थिति में, लोगों में सहम और खामोशी बरकरार रही। इस चुप्पी के नतीजे में, मुझे डर है कि वास्तविक धरातल से मिलने वाली खुफिया जानकारी काफी हद तक कम हो जाएगी और इससे सुरक्षा बलों की अभियान-क्षमता पर असर पड़ेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान, कुख्यात आईएसआई और आतंकी संगठनों के प्रयास लगातार जारी हैं डांवांडोल हुई अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा रापाकिस्तान की अंदरूनी हालत बिंगड़ती जा रही है। कुछ हद तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बनाई अस्थिरता के बीच, पाकिस्तानी व्यवस्था के राजनीतिक और न्यायिक अंगों में आपसी तनातनी जारी है। इस सबके बीच पाकिस्तानी सेना गढ़बड़ी भरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं और प्रभावशाली घोट करने के लिए सही घड़ी बैंटजार में है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रस्तावित भारत यात्रा इसमें उत्प्रेरक का काम कर सकती है कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान का संकुचित रवेया औ भारत में आतंकी गतिविधियों को एक बार पुनः विशेष मदद देकर बढ़ाने के काम से कश्मीर में शांति प्रतुलनात्मक असर होकर रहेगा। इसके साथ ही, हाल ही में इस्लामिक राष्ट्रों का संगठन पाकिस्तान की सहायता करने के फिर से आगे आया है। गोरतलब है कि पाकिस्तान के चलाने वाला धूर्त तंत्र हमेशा सभी पक्ष से मिलकर खेलता रहता आया है और कि सी न कि सी तरह ह अपने प्रासंगिकता बना ही लेता है। इस क्षेत्र को लेकर अमेरिका का अपना एक एजेंडा है, जिसके लिए उसे पाकिस्तान अड्डों की जरूरत है। चीन अपने ढंग से उल्लू सीधा करने वाला है। अरब जगत पाकिस्तान को एक साथी मानता है (परमाणु शक्ति संपन्न एकमात्र इस्लामिक राष्ट्र होने के बजह से)। भारत के प्रति चीन के शाश्वतार्थी रवेये औ कश्मीर पर नीति की वजह से स्थितियां आगे और जटिल बन जाती हैं। चीन भारत को एक अत्यं और दीर्घकालीन प्रतिद्वंद्वी मानता आया है और अपनी नीतियां उसी वें मुताबिक ढालता है। इस क्षेत्र को लेकर उसकी विशेष मांस है, जो एकदम स्पष्ट है और यह लदाख को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाले बेल्ट एंड रोड के रूट में साफ परिलक्षित होती है। जम्मू-कश्मीर का राजकीय रुतबा बदलने और उसके बाद वास्तविक सीमा नियंत्रण रखा पर घटनाक्रमों को लेकर चीन ने काफी जोर-शोर से एतराज जताया था। एक तरफ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विशाल भूभाग

यीनी नियंत्रण के नीचे है तो वहीं दूसरी ओर वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक रुख कायम रखे हुए है। पहले ही डेपसाग मामले पर कोई प्रगति नहीं हो पाई तिस पर अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को भी बीच में स्थिटा जा रहा है। लिहाजा हमें अपनी सतर्कता बढ़ाने और कायम रखने को मजबूर होना पड़ेगा, अपने स्रोतों का सुदृढ़ीकरण और उनमें गुणात्मक वृद्धि करनी होगी और कूटनीतिक कौशल को धार देनी होगी। इस तमाम परिवृद्ध्य के आलोक में, गंवाने को समय नहीं है। पहले ही अंतर सेना खींचतान, जग में वास्तविक कमान किसके हाथ हो और भर्तियों को लेकर बहुत वक्त व्यर्थ हो चुका है। यह समय बड़ी-बड़ी बातें करन का नहीं बल्कि निर्णय लेने और क्रियान्वयन का है, नीतियों और काम कर दिखाने की जगह बड़ी-बड़ी बातें नहीं ले सकती। जहां तक पुंछ की घटना की बात है, इसमें संबंधित सेना की इकाई की कोताही की भनक आ रही है—एक अकेला सैनिक ट्रक, कोई सुरक्षा आवरण नहीं, न ही रूट को पूर्व निगरानी से निरापद बनाया, कोई खुफिया सूचना नहीं और हमले के बाद देर से की गई प्रतिक्रिया, इस ओर झिशारा करते हैं। इस सीमांत क्षेत्र में अधिकांश बाइंडे गुर्जर समुदाय से हैं और दोनों मुल्क इनका इस्तेमाल करते आए हैं। सवाल यह है : बैहतर खिलाड़ी कौन निकला? पुख्ता खुफिया सूचना और सुरक्षा बलों की निगरानी से स्थिति को बैहतर ढंग से संभाला जा सकता था। घाटी में पसरी चुप्पी, विशेष रूप से एक समुदाय को निशाना बनाने वाले व्यावसायिक कठितों की उपरिथि, पहले के मुकाबले बड़ी घुसपैठ और घाटी से जुड़े जम्मू के इलाके में आतंकी गतिविधियां होना, पाकिस्तान की पीठ पर इस्लामिक राष्ट्रों का हाथ और चीन की चालें—यह बड़े स्तर पर आतंकी गतिविधियां चलने का पूर्व-संकेत है। हमारी प्रतिक्रिया में, अधिक जोर नीतियों की सही रूपरेखा तय करने, सोच-विचार कर की गई कार्रवाई और सघन राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रयासों की ओर होना चाहिए। यह तमाम मोर्च, यदि सक्रिय किये जाएं तो परिणाम अवश्य मिलेगा—समय है यह कर दिखाने का।

# जम्मू एवं कश्मीर बन रहा है भारत में निवेश का नया केंद्र

(लेखक-प्रह्लाद सबनानी )

ऐसा कहा जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 लागू करना तत्कालीन नेहरू सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, यद्योंकि इसके कारण जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों का अत्यधिक नुकसान हुआ है। दरअसल पूरे देश में नागरिकों के हितार्थ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा था। साथ ही, इन क्षेत्रों का विकास भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि अत्यधिक आतंकवाद के कारण इस क्षेत्र में कोई भी उद्योगपति अपना निवेश करने को तैयार नहीं होता था। धारा 370 को लागू करने के कारण जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को आर्थिक नुकसान के अलावा राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में पूरे भारत को ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार को रक्षा, विदेश एवं संचार जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के कानून जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता था। अतः भारत सरकार के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। इसका परिणाम यह निकलता था कि भारत के अन्य राज्यों से कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर जमीन या सम्पत्ति नहीं खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय तिरंगा के अलावा एक अलग राष्ट्रीय ध्वज भी होता था, इसलिए वहाँ के नागरिकों द्वारा भारतीय तिरंगा के समान नहीं करने पर उन पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के सम्बंध में भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि कोई आदेश दिया जाता था, तो वहाँ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे इसका पालन करें। जम्मू और कश्मीर उसके कश्मीरी होने का अधिकार छिन जाता था। इसके विपरीत यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान में रहने वाले किसी व्यक्ति से निकाह करती थी, तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई असर नहीं होता था। साथ ही, कोई पाकिस्तानी नागरिक यदि कश्मीरी लड़की से शादी करता था और फिर कश्मीर में आकर रहने लगता था तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता भी प्राप्त हो जाती थी। यह किस प्रकार के नियम बनाए गए थे जिनके अनुसार एक भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता था परंतु एक पाकिस्तानी नागरिक यहाँ बस सकता था और आतंकवाद फैला सकता था। कुल मिलाकर धारा 370 के बाले, जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को लाभ के स्थान पर नुकसान ही अधिक उठाना पड़ा है। परंतु, केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इस क्षेत्र के नागरिकों को देश में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने एवं आतंकवाद को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से दिनांक 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को कानूनी रूप से खत्म कर दिया था। केंद्र सरकार का यह फैसला सचमुच में बहुत दूरदर्शी साबित हुआ है क्योंकि धारा 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू एवं कश्मीर में कई बदलाव दृष्टिगोचर हैं। अब केंद्र के समस्त कानूनों एवं अन्य कई अर्थिक योजनाओं को वहाँ लागू कर दिया गया है इससे आम नागरिकों को बहुत सुविधा एवं लाभ हुआ है। आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है। हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। देश का यह सबसे अर्थव्यवस्था धारा 370 को लापा करने के बाद से अर्थव्यवस्था अर्थे में भारत के साथ जुड़ गया है। धारा 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में जिस तरह आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार हुआ है और केलेंडर वर्ष 2022 में रिकार्ड वृद्धि के साथ 26 लाख से अधिक पर्यटक वहाँ पहुंचे हैं। भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से वर्ष 2019 तक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया था, जबकि पिछले केवल 3 वर्षों में यह चार गुना बढ़कर 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना का भी तेजी से विकास हो रहा है। 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 15 नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इस सबसे स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। हाल ही में पिछले दिनों श्रीनगर के सेमपोरा में विदेशी निवेश से निर्मित होने वाले 250 करोड़ रुपये की लागत के एक मॉल की आधारशिला उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने रखी। यह जम्मू एवं कश्मीर में विदेशी पूँजी से बनने वाला प्रदेश का पहला मॉल होगा, जिसे 2026 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है। दुबई का एम्मार समूह इसका निर्माण कर रहा है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर में डेढ़ सौ-डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत वाले एक-एक आईटी टावर का विनिर्माण भी एम्मार समूह कर रहा है। यह इसका प्रमाण है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की बदली परिस्थितियों में जम्मू-कश्मीर में भी विदेशी निवेश आ रहा है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के मुताबिक, नई औद्योगिक नीति आने के 22 महीनों में 5,000 से अधिक देशी तथा विदेशी कार्पोरेशनों के निवेश प्राप्तनाव दियाई जाएगी। देश के अंदर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसी धोषणा शायद ही पूर्व में की गई हो।

**भाजपा नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना आश्वर्यजनक**

(लेखक- सनत जैन)

पिछले एक दशक में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर, भाजपा में जा रहे थे। अब भाजपा के नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं यह पलायन क्यों हो रहा है। खासतौर से उस पार्टी में, जो एक विचारधारा से बनी हुई पार्टी है। जिसका अपना केंद्र है। सब की विचारधारा से जोड़कर भाजपा संगठन तैयार होता है। भाजपा छोड़ कर जाना और किसी अन्य दल में अपना स्थान बनाना बहुत हद तक संभव नहीं होता है। कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेष्ठा, पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्षण सावदी सहित कर्नाटक के लगभग 30

बार के सांसद, पार्टी के बड़े आदिवासी  
नेता नंदकुमार साह का पार्टी छोड़ कर  
जाना का भाजपा के लिए तगड़ा झटका  
माना जा रहा है। अगले कुछ महीनों में  
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विधानसभा  
के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और  
छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों के कारण  
ही सत्ता बनती और बिगड़ती है। नंद  
कुमार साह का पार्टी छोड़कर जाना  
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में  
असर डालने वाला है। भाजपा के  
नेताओं ने उन्हें रोकने का भारी प्रयास  
किया लेकिन वह रुके नहीं।

एथे, या बागियों को समर्थन किया गया। पहले पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को अखेत हुए, पार्टी में वापस लाने, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने का आदित वरिष्ठ नेताओं को दिया गया था। इन्होंने नेता नाराज होकर घर बैठे हैं। पार्टी नेताओं ने उन्हें मनाने में लगी हुई है।

राजनीति में पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर ले खा था। देशभर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं की कमी नहीं थी। कांग्रेस छोड़कर वर्धी जनता पार्टी के सको लेकर भारतीय जनता पार्टी में से कांग्रेस को निशाने पर ले रही

म जनता के बीच यह संदेश भेजा था, कि काग्नेस मैं भगदड़ मर्ची ग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई भारतीय जनता पार्टी में भी इसी की स्थिति देखने को मिलने लगी रतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वारा से जुड़कर भाजपा में थे। बासे ज्यादा नाराज हैं। भाजपा के विचारधारा की पार्टी नहीं रही। के नेता और कार्यकर्ता कहने के, भाजपा संगठन अब एक विधिक संगठन का स्वरूप धारण जा रहा है। भाजपा में अब धारा, कार्यकर्ताओं की कोई यत नहीं है। जिसके कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं आंदर रहा है। पिछे अंदर जो भाजपा नेता निराशा बढ़ाने को लाया जा विचारधारा है।

बाहर से पार्टी में बाहर कारण भाजपा पलायन के सकता है। जनमानस अपना विस्तृत

अंदर ही अंदर भाजपा और नेताओं में उबाल आ छले 10 वर्षों में पार्टी के परिवर्तन आए हैं। उससे आओं और कार्यकर्ताओं में रही है। पार्टी में उन लोगों का रहा है, जिनका पार्टी की सेवे कोई लेना-देना ही नहीं

आए हुए लोगों का दखल दिता जा रहा है। जिसके पापा को आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़े। भाजपा विचारधारा के कारण बीच में कई दशकों से बदल करती आई है। अब पार्टी

में बाहर से आने वाले लोगों का कब्जा, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना और विचारधारा से दूर होने का दर्द, हर प्रदेश में भाजपा संगठन में झालकने लगा है। भाजपा नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना भाजपा की ताकतवर छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। चुनाव छवि से ही जीते जाते हैं। अभी तक हवा बनी थी, कि कांग्रेस छोड़कर नेता भाजपा की ओर जा रहे हैं। अब भाजपा नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। इसका असर कर्नाटक में देखने को मिला है। भाजपा में नियंत्रण नहीं हुआ, तो आगामी चुनावों में इसका बड़ा असर, आम जनमानस के बीच में होना तय है।











